आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 16.04.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड मिलेट नीति, कीवी नीति, आपदा प्रबंधन, कृषि से समेत 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
- प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन–बीआरपी, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन–सीआरपी की भर्ती प्रक्रिया शुरू।
- राज्य में डेंगू–चिकनगुनिया से निपटने के लिए अभियान चलाया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग ने समग्र कार्य योजना लागू की।
- **और...**चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. धन सिंह रावत ने कहा –पिछले तीन वर्षों में 3 हजार से अधिक किडनी रोगियों ने निःशुल्क डायलिसिस का लाभ उठाया।
-

कैबिनेट बैठक–1

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में कल मंत्रिमंडल की बैठक में ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पालिका बनाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट नीति, कीवी नीति, आपदा प्रबंधन, कृषि से समेत 25 प्रस्तावों पर अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय स्थिति मीडिया सेंटर में बीफ्रिंग की। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी 20 लाख से अब एक करोड़ रूपये और मंडलायुक्त की एक करोड़ रूपये से पांच करोड़ रूपये खर्च करने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया। साथ ही अब सामन नागरिक संहिता में सब रजिस्ट्रार शादी और तलाक के लिए भी अधिकृत होंगे।
सचिव ने कहा कि पैक्स के कैडर सचिव की सेवाओं के लिए 1976 की नियमावली थी, अब अलग से उत्तराखंड बहुद्देश्यीय कर्मचारी सेवा नियमावली लाई गई है। उधमसिंहनगर जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यायल के लिए यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे। हर जिले में एक गांव में संस्कृत गांव के लिए प्रशिक्षक को 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।

कैबिनेट बैठक–2

कैबिनेट बैठक में प्रदेश की कीवी नीति पर निर्णय लिया गया। वर्तमान में 6 सौ 83 हेक्टेयर में 3 सौ 82 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। 2030–31 तक क्षेत्रफल 3500 हेक्टेयर करने का निर्णय लिया गया है। जिससे राज्य के लगभग 17 हजार 500 किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही वर्तमान उत्पादन बढ़ाकर 33000 मैट्रिक टन व उत्पादकता को 7.89 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस पर सरकार 50 से 70 प्रतिशत सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना सोटी और ग्रेडिंग इकाई भी इसमें शामिल होगी। इस पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
साथ ही राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन–सोटिंग ग्रेडिंग के अलावा स्टोर के लिए भी अलग से इकाई बनाने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी और कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम में प्रति एकड़ आठ लाख कोस्ट रहेगी। इस पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इससे 450 किसान लाभान्वित होंगे। जबकि महिला समूह को 300 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
वहीं सीवर सफाई के दौरान मृत और दिव्यांग होने वालों के बच्चों को भी अब छात्रवृत्ति दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा में कक्षा एक से 12 तक के बच्चों को निशुल्क पुस्तकें दी जाएगी। साथ ही उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यायल के लिए अब यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। दोपहर में वे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम को श्री वैष्णव, पौड़ी गढ़वाल जिले में जनासू सुरंग परियोजना स्थल पर जाएंगे, जहां वे ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत निर्माणाधीन सुरंग का जायज़ा लेंगे।

गाइडलाइन जारी–1

प्रदेश में डेंगू–चिकनगुनिया से निपटने के लिए अभियान चलाया जाएगा। गर्मीयों में डेंगू व चिकनगुनिया के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने समग्र कार्य योजना लागू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अंतरविभागीय समन्वय, सक्रिय चिकित्सा व्यवस्थाएं, जनजागरूकता, निगरानी और फील्ड एक्शन के लिए निर्देश जारी किए हैं। अभियान में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क

विभाग सहित कई विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि डेंगू व चिकनगुनिया जैसे मच्छरजनित रोगों की रोकथाम का पहला कदम स्वच्छता है। जब तक हम स्रोत नियंत्रण यानी सोर्स रिडक्शन नहीं करते, तब तक मच्छरों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे लगातार सफाई अभियान चलाएं और समुदाय को भी इस प्रयास में भागीदार बनाएं।

गाइडलाइन जारी–2

उन्होंने बताया कि सभी जिलों में अलग डेंगू आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएंगे, जिनमें मच्छरदानी युक्त पर्याप्त संख्या में बेड, प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी उपकरण मौजूद रहेंगे। गंभीर रोगियों के लिए प्लेटलेट्स जांच किट्स और अन्य औषधीय सामग्री की समय पर आपूर्ति अनिवार्य की गई है। इसके आलवा राज्य मुख्यालय पर क्रियाशील हेल्पलाइन 104 को पूरी तरह से जनता के लिए सक्रिय रखा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी शंका या समस्या को साझा कर सके और तत्काल सलाह प्राप्त कर सके। डेंगू के संक्रमण काल के दौरान सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जागरूकता अभियान के लिए हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में गोष्ठियों जैसे संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया शुरू

उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन–बीआरपी, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन–सीआरपी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेशभर में रिक्त कुल 9 सौ 55 पदों पर जिलेवार मैरिट तैयार कर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। भर्ती के लिये आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिये रोजगार प्रयाग पोर्टल को पुनः एक सप्ताह के लिये खोल दिया है ताकि अभ्यर्थी मांगी गई समस्त शैक्षणिक जानकारी व कार्य अनुभव को ऑनलाइन अपलोड कर सके। इस संबंध में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि लम्बे समय से लटकी पड़ी इस भर्ती को शुरू करने के लिये कौशल विकास एवं सेवायोजना विभाग से पत्राचार किया गया, जिसके उपरांत सेवायोजना विभाग की ओर से प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों का समाधान करते हुये शासनादेश में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब संशोधित शासनादेश के तहत भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड आयुष आधारित जीवनशैली का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेगा। ये बात उन्होंने समक्ष पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल से 'वन यूनिवर्सिटी–वन रिसर्च' कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण के दौरान कही। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें न केवल संरक्षित करने की आवश्यकता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थापित कर वर्तमान जीवनशैली में अपनाया जाना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि आज जब संपूर्ण विश्व आधुनिक चिकित्सा के साथ–साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की ओर भी उन्मुख हो रहा है। ऐसे समय में भारत, और खासतौर पर उत्तराखण्ड जैसे राज्य, जिनकी संस्कृति और प्रकृति स्वस्थ जीवनशैली से जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं।

निःशुल्क डायलिसिस

चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि बीते तीन वर्षों में 3 हजार से अधिक किडनी रोगियों ने निःशुल्क डायलिसिस का लाभ उठाया। इन मरीजों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना के तहत ढाई लाख से अधिक बार सफलतापूर्वक डायलिसिस कराया गया है। किडनी से संबंधित रोगों के निदान के लिये प्रदेशभर के विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहां पर 166 डायलिसिस मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार को लेकर निरंतर प्रयासरत है ताकि आम लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकें। राज्य सरकार के ठोस क्रियान्वयन व मॉनिटिरिंग के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का लाभ किडनी मरीजों को मिल रहा है। डॉ. रावत ने बताया कि किडनी रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 06 नये डायलिसिस केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरीनाग पिथौरागढ़, जिला अस्पताल बौराड़ी टिहरी, गोविंद सिंह महर राजकीय चिकित्सालय रानीखेत अल्मोड़ा, उप जिला चिकित्सालय मसूरी देहरादून और उप जिला चिकित्सालय काशीपुर ऊधमसिंह नगर शामिल है।

और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में 988 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया है। यह ख़बर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला लिखता है– नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का आरोप पत्र... सोनिया व राहुल ने संपत्ति हड़पने के लिये रची आपराधिक साजिश।

एक अन्य ख़बर पर दैनिक जागरण उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है– रिस्पना व बिंदाल नदी के आसपास बगैर नक्शा पास निर्माण पर रोक। समाचार पत्र के अनुसार राज्य सरकार ने कहा है कि रिस्पना व बिंदाल नदी के आसपास से तीस जून तक अतिक्रमण हटा लिया जाएगा।

उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णयों की ख़बर को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है– सेब, कीवी, मोटे अनाज व ड्रैगन फ्रूट की खेती पर अस्सी प्रतिशत तक की मिलेगी सब्सिडी... कक्षा एक से बारहवीं तक के दस लाख छात्रों को मिलेंगी मुफ्त कॉपियां।

देहरादून के रायपुर गैस गोदाम मामले में दायर याचिका को हाइकोर्ट ने खारिज़ कर दिया है। राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के अनुसार तपोवन रोड स्थित गैस गोदाम में बड़े ट्रकों से सिलेंडरों की आपूर्ति पर लगाई गई रोक जारी रहेगी।

उत्तराखंड में तबादलों की अधिकतम सीमा खत्म। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– प्रदेश में अब ट्रांसफर एक्ट के हिसाब से हीं होंगे तबादले, सुगम और दुर्गम क्षेत्रों में होंगे बराबर स्थानांतरण।